कचरे को नहीं जलाने का निर्देश दिया

है। एनजीटी प्रमुख न्यायमुर्ति स्वतंत्र

कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने

केन्द्रीय प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड और

अन्य को नोटिस जारी करते हुए उनसे

दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल

करने को कहा है। यह आदेश आगरा

के रहने वाले पर्यावरण कार्यकर्ता डी

के जोशी की उस याचिका पर आया

है, जिसमें उन्होंने आईआईटी-कानपुर,

जॉर्जिया प्रौद्योगिकी संस्थान और

विस्कॉन्सिन विवि के संयुक्त

अध्ययन का हवाला दिया है।

Newspaper Clips June 2, 2016

Virat Vaibhav ND 02/06/2016 P-05 प्रदूषण से पीला पड़ रहा है ताजः एनजीटी का केन्द्र को नोटिस

एजेंसी 🔳 नई दिल्ली

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने एक पर्यावरण कार्यकर्ता की याचिका पर केन्द्र से जवाब मांगा है, जिसमें उसने आरोप लगाया है कि आगरा में बड़े पैमाने पर नगरपालिका के ठोस कचरे को जलाए जाने से ताजमहल का रंग पीला पड़ रहा है। हरित अधिकरण ने नगर प्राधिकरणों को आगरा और पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील ताज के समानांतर क्षेत्र के निकट खुले में नगरपालिका के ठोस



आंसर-की जारी होगी। 12 जून को

परीक्षा आयोजित कराई है। बता दें कि जो

छात्र एडवांस की मेरिट में जगह पाएंगे

उन्हें एनआईटी और आईआईटी में

दाखिला मिल सकेगा। इससे पहले जेईई-

मेन की परीक्षा हुई थी। जेईई-मेन की रैंक

के आधार पर राज्य स्तर के इंजीनियरिंग

कॉलेजों में दाखिला होता है।

इस बार आईआईटी गुवाहाटी ने

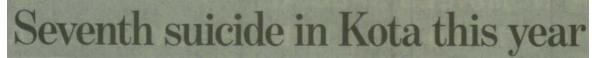
अंतिम परिणाम जारी होगा।

Hindustan ND 02/06/2016

आईआईटी में दाखिले की हुई जेईई-एडवांस की उत्तर पुस्तिका को ऑनलाइन जारी कर दिया गया है। छात्र https://portal.jeeadv.ac.in पर देख सकते हैं। 4 जून तक इन्हें देखा जा सकता है और प्रतिक्रिया दी जा सकती है। इसके आधार पर सीबीएसई 5 जून को आंसर-की जारी करेगा।

4 जून शाम चार बजे तक कॉपी हासिल की जा सकती है। छात्रों को सीधे पोर्टल पर जाना होगा। वहां लॉग इन

Hindustan Times ND 02/06/2016 P-08



HT Correspondent

letters@hindustantimes.com

JAIPUR: An engineering aspirant allegedly ended his life in Kota due to study pressure, police said on Wednesday, the seventh student to commit suicide this year in the Rajasthan town known as the coaching capital of the country.

Nirmal Yogi, 17, was found hanging from the ceiling of his hostel room on Tuesday after police broke open the door following an alert from the caretaker.

Yogi, hailing from Sawai Madhopur, was taking coaching at one of the private institutes in Kota.

Police said Nirmal Yogi had enrolled at an institute two months ago and was allegedly upset over his performance in monthly tests.

"We did not find any suicide note in his room," police officer Kaluram Verma said.

Every year, more than 1.5 lakh student from across the country enroll in the 40-odd coaching institutes in Kota to prepare for the highly-competitive entrance examinations for different professional courses.

At least 56 students studying in different institutes in the city have committed suicide in the last five years, most of them attributed to the fear of failure.

Economics Times Hindi ND 02.06.2016 P-07



प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से जनवरी में लॉन्च किए गए स्टार्टअप एक्शन प्लान का सरकार रिव्यू कर रही है। इसका मकसद यह पता लगाना है कि प्लान सही दिशा में बढ़ रहा है या नहीं। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन (डीआईपीपी) इसके डेटा जुटा रहा है और वह अपनी रिपोर्ट नीति आयोग को देगा।

अभी तक उठाए गए कदमों की समीक्षा के लिए डीआईपोपी के अधिकारी दो मीटिंग कर चुके हैं। स्टार्टअप्स के लिए बेहतर माहौल बनाने के मकसद से हाल ही में पेटेंट से जुड़े रूल्स में बदलाव किया गया है। डीआईपीपी ने पेटेंट एप्लिकेशंस दाखिल करने में स्टार्टअप्स की मदद के लिए 280 एक्सपर्ट्स का एक ग्रुप भी बनाया है। इसमें वकील और कंसल्टेंट्स शामिल हैं।

संशोधित रूल्स में पेटेंट रजिस्ट्रेशन के लिए सर्विसेज में तेजी लाने का भी प्रावधान है। इनमें स्पेशल बेनेफिट्स के लिए 'स्टार्टअप' की परिभाषा भी दी गई है।

इनक्यूबेशन की राज्य के आधार पर कैपेसिटी का पता लगाने के लिए सरकार देशभर में इनक्यूबेशन सेंटर्स की जानकारी जुटा रही है। केंद्र चाहता है कि छोटे शहरों को स्टार्टअप्स ठिकाना बनाएं। इसके लिए खासतौर पर पूर्वोत्तर राज्यों पर जोर दिया जा रहा है।

डीआईपीपी ने हाल में पूरे स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए सिंगल-प्वाइंट कॉन्ट्रैक्ट की खातिर स्टार्टअप पोर्टल और मोबाइल ऐप के साथ स्टार्टअप हब भी लॉन्च किया है। पोर्टल से स्टार्टअप्स को स्टार्टअप एक्शन प्लान के तहत दिए गए टैक्स बेनेफिट्स लेने में मदद मिलेगी। स्टार्टअप एक्शन प्लान के इंसेंटिव्स में तीन वर्षों के लिए टैक्स हॉलिडे और इंस्पेक्टर राज से मुक्ति के अलावा कैपिटल गेन्स टैक्स में छूट शामिल है। सरकार ने स्टार्टअप्स की फंडिंग के लिए 10,000 करोड़ रुपये के फंड की भी घोषणा की है।



स्टार्टअप एक्शन प्लान लॉन्च करने के चार महीने बाद सरकार ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (आईआईटी) के 93 रिसर्च प्रपोजल्स की पहचान इनोवेशन की क्षमता या इंडस्ट्री पर संभावित असर की वजह से की है। इन प्रपोजल्स को इंडस्ट्री और बिजनेस के लिए फायदे के आधार पर चुना गया है। डीआईपीपी इन प्रपोजल्स पर काम बढ़ाने के लिए आईआईटी और इंडस्ट्री के बीच मददगार के रोल में होगा। सरकार ने आईआईटी स्टूडेंट्स को 'अच्छी क्वॉलिटी' की रिसर्च में मदद के लिए सालाना 250 करोड़ रुपये का फंड रखा है। इसमें एचआरडी मिनिस्ट्री का 50 पसेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री का 25 पसेंट और डीआईपीपी का 25 पसेंट योगदान होगा।

Rajasthan Patrika ND 02/06/2016 P-14



बिना पासपोर्ट पकड़े अफ्रीकी व पाक नागरिकों के साथ रखा

भारतीय दूतावास से शिकायत, सोशल मीडिया पर आलोचना ^{रोम @ पत्रिका}

百百万 rajasthanpatrika.com फ्रांस की एक कंपनी में इंटर्नीशिप कर रहे आईआईटी पास तीन भारतीय छात्रों को इटली में सोमवार को 10 घंटे हिरासत में रखा गया। ट्रेन के इंतजार कर रहे तीनों को उत्तरी इटली केवेंटिमिग्लिया में पासपोर्ट की जांच के नाम पर रोका गया। स्थानीय सुरक्षाकर्मी उन्हें बिना पासपोर्ट वाले कुछ अफ्रीकी और पाकिस्तानी नागरिकों के साथ हवाई जहाज से 110 किलोमीटर दूर बारी शहर ले गए। दस घंटों की प्रताडना के बाद छात्रों ने अपने परिजनों, प्रोफेसरों और दोस्तों से किसी तरह संपर्क किया। सभी के बढते दवाब के बाद उन्हें छोड दिया गया। छात्रों ने बुधवार को भारतीय दूतावास में इस घटनाक्रम की लिखित शिकायत की। हालांकि भारतीय



अक्षित गोयल और अपनी मां के साथ उदय कुसुपति।

वीकेंड पर पहुंचे थे घूमने

तीन छात्रों में से एक उदय कुसुपति आईआईटी मुंबई और अक्षित गोयल और वीपक भष्ट आईआईटी दिल्ली के छात्र हैं। ये तीनों फ्रांस की एक कंपनी में मई से इंटर्नशिप कर रहे हैं और वीकेंड पर इटली में पोर्ट ऑफ जिनोआ जा रहे थे।

अधिकारियों ने इटली में छात्रों के पकड़े जाने पर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन छात्रों के दोस्तों का कहना है कि उन्हें ऐसे यात्री समूह का का हिस्सा मान लिया गया था जो बिना दस्तावेजों के देश में घूम-फिर रहे थे। सभी फिलहाल रोम में हैं। मामले को नस्लवाद से जोड़कर देखा जा रहा है। छात्रों को इंटर्नशिप पूरी करने के लिए वापस फ्रांस भेजने की तैयारी की जा चुकी है।



पहले भी हुए संबंध खराब

सोशल मीडिया पर शेयर हो रहे मेरोज को इटली में रंगभेद से जोड़कर देखा गया। इसके पहले भी इटली और भारत के संबंध खराब हो चुके हैं। 2012 में इतालवी मरीन्स द्वारा भारतीय मछुआरों की हत्या करने के बाद रिश्ते बिगड गए थे।

इसलिए हुई घटना...

इटली के कार्अंसेल जनरल उगो कियारलातानी ने कहा, 'इटली में रंगभेद नहीं। बड़ी संख्या में सीरिया के लोग रोजाना इटली आ रहे हैं। संभवतया इसी वजह से घटना हुई। आईआईटी ऑन कैम्पस इनसाइट मैगजीन के एडिटर श्रीरंग जावडेकर ने कहा कि सुरक्षाकर्मियों के अंग्रेजी न बोल पाने के कारण ऐसा हुआ।



यही हैं इटली का मश्रहर पोर्ट ऑफ जिनोआ।

विदेश मंत्रालय की पहल पर छुटे

छात्रों ने अपने दोस्तों से सोशल मीडिया के जरिए संपर्क साधा। वोस्तों ने भारतीय विदेश मंत्रालय से संपर्क किया। इसके बाद विदेश मंत्रालय ने इटली दूतावास से बात की। इसके बाद ही छात्रों को छोडा गया।

इंटर्नशिप के लिए गाडडलाइन

सोमवार को हुए इस घटना को देखते हुए आईआईटी मुंबई ने निंदेश जारी कर छात्र समूहों को दूसरे देशों में इंटर्नशिप के लिए सुरक्षित ट्रैवल गाइड तैयार करने को कहा। निंदेश में कहा गया है कि सभी लोकतांत्रिक देशों के मूल अधिकारों की सूची अपने पास रखें।

IIT alumni come up with app to help accident victims

http://paper.hindustantimes.com/epaper/viewer.aspx

APP USERS CAN LOCATE THE NEAREST POLICE STATION AND THE PHONE NUMBERS OF OFFICIALS IN EMERGENCY SITUATION ARISING OUT OF ACCIDENT

JAIPUR: To assist the road accident victims, former students of Indian Institute of Technology (IIT) have come up with a mobile application – 'Ruly' – that sends distress message in Morse code. With Ruly, app users can locate the nearest police station and the phone numbers of officials in emergency situation arising out of accident. Mobile users can download the app from Google Store. Ruly's cofounder Ram Prasath, an alumnus of IITKharagpur, believes the app has the potential to go beyond the Centre's plan to launch a uniform emergency number across India. "We are trying to provide an allinone service that will help distressed users in remote locations. The app works in all states and union territories. It has a huge database of contact numbers of police, medical and legal services," he said. App users can activate the app's inbuilt emergency feature by pressing the power button of their phones twice. "Ruly uses the GPS location of phone to find the closest police station. It lets you add up to three emergency contacts who will receive an SOS message in emergency situation," said Ram. A harrowing road accident in 2014 involving Ram and his friends - cofounders Nishant Trivedi of IIT Khargapur and Ujjwal Singh of IIT Kanpur – prompted them to come up with the mobile app. "In 2014, while we were travelling in Punjab, we met with an accident in the middle of the night. It took 56 hours for police to turn up. That is when the idea hit us that we need an app that provides needful data on the go," Ram said. Originally launched as a legal service provider, Ruly app is now an allinone service provider which the developers plan to widen the app's reach in Tier2 cities through their network of lawyers. "At this moment, we have a network of 150 lawyers based in large cities. In due time, we intend to widen our network in tier 2 cities as well," another cofounder Ujjwal Singh said.

Riding solar-powered bicycle, IIT innovator reaches Jodhpur

http://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/Riding-solar-powered-bicycle-IIT-innovator-reaches-Jodhpur/articleshow/52545804.cms



JODHPUR: With a concern for depleting conventional energy resources and promoting solar energy as an alternative to this impending crisis, an IIT Mumbai alumnus Sushil Reddy has set off on a 7000 km long journey through five states of the country with his three friends on a solar-powered electric bicycle.

Started from IIT Mumbai on May 8, Reddy reached Jodhpur on Wednesday covering 2100 km and interacted with the students of Euro School and MBM Engineering College addressing their confusions and replying to the queries pertaining to solar energy.

"The solar energy has been touted to be not only a green energy but the energy of future also. Even the Indian

government has a huge stake and projections about production of solar energy, but on the grass root level, there is pathetic dearth of knowledge and awareness about the technology," said Reddy.

So, with this in mind and considering a huge potential in the field of solar energy in terms of employment scope in the time to come, Reddy has not only been spreading awareness among the people enroute about the solar energy but also equipping them with required technical know-how to enable them to use the same in different applications at their end.

Having completed his BTech from IIT Mumbai in Energy Science in 2013, Reddy left a startup, founded by a professor of the IIT Mumbai, with which he was associated for the past 3 years, to embark upon this journey.

With his three friends, Rajendra Bhaskar, who is currently in his 3rd semester of IIT Mumbai in energy science; Krunal Tailor, with masters in renewable energy and Himanshu Singh, a technical expert; Reddy is training people on the way on how to design and install a solar system for specific use.

Riding on this cycle, a prototype designed and developed by him in about four months, Reddy is being accompanied by Bhaskar, who has been riding with him on a normal bicycle, whereas the other two have been moving in a support vehicle, travelling 100-120 km per day to cover the entire ride in 70 days.

Reddy said that once they wind up this, what they call a Sun Pedal Ride, the team will begin work on coverting this prototype into a reality keeping the common man in mind, which should be cheaper and more practical with a view to cut down upon the consumption of the conventional fuel.

IIT-Gn grads also faced job deferrals

http://timesofindia.indiatimes.com/city/ahmedabad/IIT-Gn-grads-also-faced-job-deferrals/articleshow/52545957.cms

Ahmedabad: Not only IIM-A, where in Flipkart had first hired 18 students and later deferred the joining dates, Indian Institute of Technology, Gandhinagar (IIT-Gn) had also faced similar issues in past. However, the Gandhinagar-based institute maintained that the earlier incident did not have far-reaching effect.

According to a statement from IIT-Gn, "There have been a few instances in the past regarding delaying of joining dates and reducing pre-agreed compensation to students which were, however, handled appropriately."

"The intensities were not worth bringing it up as an issue. For that matter, we have been fortunate enough to share a very good understanding with our recruiters and avoid uncomfortable disagreements. Once in a while, changes in joining dates and compensation have been, there but have been handled on a case-to-case basis considering the interests of all the involved parties," it said.

The institute's reply was to the question of whether any recruiters had backed out after promising jobs to IIT-Gn students.

On if IIT-GN was taking any precautions to avoid a Flipkart-like issue, it said, "IIT-Gn tries to consider the overall profile of companies that visit its campus including market value, capitalization, past record and future growth prospects."

"While such incidences may not be completely avoidable, scrutiny of potential employers along with pre-placement deliberations to build trust helps minimize such issues," an email reply from IIT-GN said.

Page **6** of **7**

These issues do not solely concern IIM-A and IIT-Gn. At Ahmedabad's premier strategic marketing and communications institute, Mica, two startups backed out after hiring a candidates during placements this March.

Madhukar Kamath, chairperson of the Mica governing council, had earlier said, "We witnessed an unusual scenario in placements this year, when our best students were offered jobs with excellent salaries, but later two startups backed out - one cited its failure to garner the needed funds for the start-up itself, while another curtailed the package offered to a candidate."

IIM-A ties up with tech trainers for e-learning courses

http://timesofindia.indiatimes.com/city/ahmedabad/IIM-A-ties-up-with-tech-trainers-for-e-learningcourses/articleshow/52546649.cms

Ahmedabad: The Indian Institute of Management, Ahmedabad (IIM-A) on Wednesday has announced it will launch several E-learning programmes in the next few months. The city-based premium institute has tied up with NIIT and Hughes to deliver education in the form of synchronous studio-to-classroom programmes.

This initiative comes after recognizing that management education is going through dramatic changes, especially with regard to infusion of technology challenging the traditional content delivery model, said officials of the institute.

IIM-A signed an agreement with Hughes Communication India limited, which is a networking services company on Wednesday. The an agreement with NIIT Limited, a leading management training company, was reached in May.

"Information technology is creating significant disruptions and opportunities in the higher-education sector. Increasingly, delivery of high-quality management education is becoming feasible through technology. IIM-A is committed to innovating and leveraging technology to provide the best quality educational experience to leaders that make a difference," said Professor Ashish Nanda, director of IIM-A.

Rahul Patwardhan, CEO, NIIT Ltd said, "We started working with IIM-A in 2006, to offer quality executive management programmes to young professionals across the country by leveraging NIIT's pioneering Synchronous Learning Technology."

"As a leading player in educational technology in India, NIIT has been at the forefront of technological and pedagogical innovations in learning, keenly aware of challenges the higher education sector faces," Patwardhan said. "Taking our association with IIM-A forward, we will continue to work towards developing innovative learning models to deliver their management programmes at scale, by providing best-in-class technology-based solutions," Patwardhan added. "Hughes has been the pioneer and at the forefront of Interactive Onsite Learning (IOL) technology in India, since 2002, with more than 25,000 alumni. Hughes is proud to be associated with IIM-A, in their quest to spread premium class-apart learning to remote locations in India. Hughes looks up to this tie-up to take top curricula, programmes and of IIM-A to prospective students across India," said Partho Banerjee, president and managing director of Hughes.

"NIIT and Hughes are well-known names in distance education. IIM-A selected the institutes after a thorough selection process," said a statement from the IIM-A.

MANAGEMENT EDUCATION

Close five-year integrated MBA courses, govt tells B-schools

AICTE has, in a circular, directed institutions not to enrol students to such courses for the 2016-17 academic year

BY PRASHANT K. NANDA prashant.n@livemint.com

NEW DELHI

The central government has decided to close down five-year integrated or dual-degree master of business administration (MBA) programmes offered by many universities and independent management schools in India. The government had previously closed down four-year undergraduate degree courses in academic year 2014-15.

A circular issued by the country's technical education regulator All India Council for Technical Education (AICTE) said such courses were "not in line with the UGC-approved programmes." The University Grants Commission (UGC) is the country's top higher education regulator.

"The AICTE has decided the following: the dual degree courses have been closed (sic) and no fresh admission should be permitted from AY (academic year) 2016-17," said a circular issued to all institutions.

It has directed institutions not to enrol students to such courses for the 2016-17 academic year. Students currently enrolled in such courses will be allowed to exit the course after the end of three years, the circular said.

Ironically, such courses were approved by AICTE in 2012-13 to suit the different needs of the industry.

The five-year integrated course had an exit option at the end of three years with a degree



Closing the doors: AICTE said such courses were not in line with the UGC-approved programmes.

called bachelor of management (BM), and after four years with bachelor of applied management. On completion of five years, students were given master's degree in applied management.

Former AICTE chairman S.S. Mantha, who had signed off on the programme, defended his four-year-old decision. "I don't think, the integrated course has flouted any norms. What they have now moved is to shut the five-year integrated programmes," Mantha said, pointing out that the circular clearly mentions that existing students will not face any problem.

The integrated course was intended to provide an undergraduate degree at the end of three or four years, followed by a master's degree in five years. The regulator had then cited three key objectives for starting such courses: a) To educate and groom the students to get entry-level managerial positions in manufacturing/services organizations or to start and run own ventures with good business knowledge.

b) To facilitate the development of students to take up growing challenges and find and implement solutions that are environmentally viable, ethically correct and socially acceptable.

c) To provide for job opportunities at different levels of management within organizations starting at supervisory level in small and medium enterprises and middle level management in large PSUs and MNCs.

"What we had done four years back goes well with the present government's push for start-ups. In my view, such courses can create employable workforce for Prime Minister Narendra Modi's Start-up India mission," Mantha added Over 10,300 institutions, including more than 3,400 B-schools, come under the purview of AICTE. But there is no exact data on how many institutions offer such courses and how many students are enrolled.

Industry insiders said that since the course is just four-yearold, less than 100 schools offer such courses. "The number of students pursuing such courses are estimated to be less than 10,000," said Harivansh Chaturvedi, alternate president of education promotion society of India, a federation of private professional education providers in India.

Indian Institute of Management (IIM)-Indore also offers a five-year integrated management course but IIMs don't come under the purview of AICTE.

In the latest circular, the AICTE said it will safeguard the interests of the students who have enrolled in such courses since 2012-13.

"There will be an exit option at the end of three years for the students, who have joined the dual degree courses in 2015-16 and prior to that, by awarding a BBA (bachelor of business administration) degree instead of a BM degree," the circular said.

C. Raj Kumar, vice-chancellor of O.P. Jindal Global University, a private university in Haryana that offers a five-year integrated MBA course, said he is yet to receive a circular from AICTE.

"As a university, we are governed by the UGC, not by AICTE. I am not sure, whether our integrated course will have any impact because of the AICTE directive. Even if it does, it will not impact existing students," Kumar said, adding that there is demand for such